

## भुड़कुड़ा मंच से योगी जी द्वारा 'धर्मनिरपेक्षता' की पुनर्परिभाषा

डॉ धर्मेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव  
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 अक्टूबर को गाजीपुर की यात्रा पर थे। जनपद स्थित दो प्राचीनतम सिद्धपीठ -सगुण उपासना के केंद्र हथियाराम मठ और निर्गुण उपासना की परंपरा के वाहक भुड़कुड़ा मठ उनकी इस यात्रा के दो महत्वपूर्ण पड़ाव बने। पहले उन्होंने सिद्धपीठ हथियाराम स्थित माँ वृद्धाम्बिका का अर्चन पूजन किया और फिर उन्होंने सिद्धपीठ भुड़कुड़ा में स्थित 10सिद्ध संतों की समाधियों पर शीश नवाया। तदुपरांत श्री महंथ रामाश्रय दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय भुड़कुड़ा में स्थापित सिद्धपीठ के दसवें पीठाधीश्वर श्री महंथ रामाश्रय दास जी की मूर्ति का अनावरण किया। यहाँ तक का सारा घटनाक्रम योगी जी के वैयक्तिक आध्यात्मिक प्रतिबद्धता और संत-मत के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक लग रहा था।

किन्तु पी.जी. कॉलेज भुड़कुड़ा के मंच से योगी जी ने भारतीय राजनीति के एक मौलिक सिद्धांत 'धर्मनिरपेक्षता' को चुनौती देकर जो वैचारिक तीर छोड़ा, वह केवल एक राजनीतिक भाषण का अंश मात्र नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान का एक प्रबल आह्वान था। एक ऐसे विमर्श की शुरुआत जिसमें योगी जी ने 'धर्मनिरपेक्षता' को 'भारतीयता' के पैमाने पर कसने की चुनौती दी। एक व्याकुलता दिखी देश के संविधान और संस्कृति के मध्य एक गहन संतुलन स्थापित करने की और अनमनस्यता का भाव भी कि एक अनचाही अवधारणा की परिधि में कार्य करना पड़ रहा है।

वक्तव्य का संदर्भ

गाजीपुर, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित वह भौगोलिक बिंदु है जहाँ राजनीति, धर्म और संस्कृति का त्रिवेणी बनता है। 'लहुरी काशी' के उपनाम से संज्ञायित यह वही जनपद है जहाँ के लोकप्रिय नेता और वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी प्रदेश में मुख्यमंत्री चयन के समय योगी जी के प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरे थे। यह वही गाजीपुर है जहाँ के मुख्तार अंसारी के अंत को प्रदेश सरकार ने माफियाराज के अंत के रूप में प्रचारित किया था। किन्तु आश्चर्यजनक रूप से योगी जी ने ऐसे किसी भी विषय का सन्दर्भ नहीं लिया वरन गाजीपुर की धरती का सन्दर्भ महर्षि विश्वामित्र से लेते हुए जब बिहार के जिले बक्सर को अपने उद्बोधन का विषय बनाया तो जाहिर हुआ कि सन्देश का सन्दर्भ सेकुलरिज्म के फैशनेबल शब्द पर प्रहार के साथ ही साथ बिहार चुनाव की पीठिका तैयार करना भी है।

हाल के वर्षों में हथियाराम मठ स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वैचारिक नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना है — जहाँ पिछले वर्षों में संघ प्रमुख मोहन भागवत दो बार प्रवास कर चुके हैं। स्वतः ये दोनों पीठ जिस जखनिया विधान सभा क्षेत्र में आते हैं वहां अभी तक कमल नहीं खिल सका है ऐसे में गाजीपुर का यह मंच चुनावी संदेश देने के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत उपयुक्त था और योगी जी ने इस मंच का उपयोग भी खूब किया। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि योगी का यह भाषण एक सुनियोजित राजनीतिक संदेश था — एक ऐसा संदेश जो 'धर्मनिरपेक्षता' की पुनर्व्याख्या के माध्यम

से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जमीन को पुनः सशक्त करने का प्रयास कर रहा था। साथ में अपने तात्कालिक राजनीतिक हितों का प्रबंधन भी।

‘धर्मनिरपेक्षता’ भारतीय शब्द नहीं

हाल के दिनों में ‘धर्म-निरपेक्षता’ का शब्द भाजपा और संघ के प्रतिनिधियों के निशाने पर रहा है किन्तु कदाचित्त यह पहला अवसर रहा होगा जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री भारतीय संविधान के एक प्रमुख सिद्धांत ‘धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा’ के विरुद्ध इतना मुखरित रहा हो। उनका यह कहना कि “यह शब्द न तो भारतीय संस्कृति के मूल्यों से मेल खाता है और न ही यह देश की मिट्टी का मूल भाव है। या इस शब्द की संवैधानिक प्रविष्टि पर सीधा हमला बोलना और यह कहना कि “धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संकल्पना में था भी नहीं। इसे चोर दरवाजे से तब डाला गया जब बाबा साहेब (डॉ. अंबेडकर) के संविधान को कुचलने का कुत्सित प्रयास चल रहा था।” यह बताता है कि योगी जी के मन में संविधान के कुछ प्रावधानों के प्रति कितना गहरा असंतोष है और लोक सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 सीट क्यों चाह रही थी।

“भारत की संस्कृति धर्म परायणता की रही है, भारत में धर्म और राज्य कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं रहे। भारत का प्रत्येक सनातनी अपने राष्ट्र को प्रेम करता है वह सबसे पहले भारतीय है। ऐसे में भारत के सनातन मूल्यों से ‘धर्मनिरपेक्षता’ को नहीं जोड़ा जा सकता।” योगी के इस कथन के दो निहितार्थ निकाले जा सकते हैं- प्रथम, ‘भारतीयता’ को धर्म-पंथ से ऊपर स्थापित करना; और द्वितीयक ‘धर्मनिरपेक्षता’ को एक पश्चिमी विचार के रूप में चिन्हित करना, जो भारतीय सांस्कृतिक मर्म से असंगत है और इस आधार पर पूरी तरह से खारिज करने योग्य भी। दरअसल, योगी जी ‘धर्म’ की जिस भारतीय परिभाषा को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं उसके अनुरूप धर्म केवल पूजा-पद्धति नहीं, बल्कि कर्तव्य, सदाचार और नैतिकता का पर्याय है। इस दृष्टिकोण से ‘धर्म से निरपेक्ष’ होने का अर्थ है ‘कर्तव्य

से निरपेक्ष’ होना—जो किसी भी राष्ट्र के लिए अराजकता का मार्ग प्रशस्त करता है इसलिए त्याज्य है।

संवैधानिक इतिहास

धर्मनिरपेक्षता पर योगी की टिप्पणी का संवैधानिक अवलंब भी था। वास्तव में भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के तत्वों का समावेश स्वतंत्रता संग्राम के दो ‘राष्ट्रीय आघातों’—देश का धर्म के आधार पर विभाजन और महात्मा गांधी की हत्या—से प्रेरित था। संविधान निर्माताओं ने भारत की सामासिक संस्कृति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए अलग-अलग अधिकार और ‘पर्सनल लॉ’ देने की व्यवस्था की थी। किंतु, ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द मूल रूप से संविधान में नहीं था। इसे 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में समाहित किया गया था। विडंबना यह रही कि “जब से इस शब्द ने संविधान में प्रवेश किया तभी से धर्मनिरपेक्षता के लिए संकट और धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्नचिह्न दोनों ही लगाये जाने लगे”।

शब्द और आत्मा का टकराव

संविधान में प्रवेश के बाद धर्मनिरपेक्षता राजनीतिक दलों के लिए एक ‘फैशन’ बन गई, जिसका उद्देश्य खुद को धर्मनिरपेक्ष और विरोधी को ‘साम्प्रदायिक’ साबित करने की होड़ में प्रयोग करना था। राजनीति के क्षेत्र में इसकी सार्थकता को एक ‘संकीर्ण और नकारात्मक समीकरण’ में बांधा गया, जिसे ‘साम्प्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता’ के फलक पर ही देखा गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य महज साम्प्रदायिकता का विरोध रह गया। इतना ही नहीं, यह शब्द “वोटों की राजनीति” के चलते न केवल सीमित हुआ, बल्कि विकृत भी हुआ, और “तमाम भ्रष्टाचार और कुशासन पर पर्दा डालकर जनता के बीच चुनाव में उतरने का यह एक अच्छा उपक्रम बनता रहा”।

योगी आदित्यनाथ इसी विसंगति पर प्रश्न उठाते हैं। उनके अनुसार, भारत में ‘धर्म’ जीवन का आधार है — वह आस्था का नहीं, बल्कि आचरण का नियम है। अतः ‘धर्म से दूरी’ का विचार भारतीय मनीषा के विपरीत है। वे कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर यदि राज्य अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कटेगा, तो समाज अपनी नैतिक दिशा खो देगा। उनके अनुसार, “धर्मनिरपेक्षता की आड़ में जाति की नंगी राजनीति खेलने की स्वतंत्रता हासिल की गई है” — यह एक गहरी राजनीतिक टिप्पणी है, जो बताती है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक अर्थ समाज में धार्मिक समरसता नहीं, बल्कि चुनावी समीकरणों का निर्माण बन गया। योगी आदित्यनाथ का यह आरोप कि धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए हुआ है, भारतीय राजनीति की एक कड़वी सच्चाई को उजागर करता है।

‘सेक्युलरिज्म’ का भारतीय अनुवाद

योगी की आपत्ति का एक और कारण भारत में ‘सेक्युलरिज्म’ का शाब्दिक अनुवाद ‘धर्मनिरपेक्षता’ किया जाना भी है — विद्वान इसे ‘पंथ-निरपेक्षता’ कहना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसका निहितार्थ यह है कि राज्य किसी विशेष पंथ का पक्ष नहीं लेगा, परंतु धर्म-विरोधी भी नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ इस शब्दार्थ संकट को गहराई से महसूस करते हैं। उनके अनुसार, ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द का प्रयोग धर्म विरोधी भाव के साथ किया गया, जबकि भारत में राज्य को धर्म के प्रति न तटस्थ होना है न विरोधी — बल्कि उसे ‘सर्वधर्मसमभाव’ की नीति पर चलना है। यह भाषाई भ्रम केवल शब्द का नहीं, बल्कि विचार का भी है। पश्चिमी राजनैतिक शब्दावलियों को ज्यों का त्यों भारतीय संदर्भ में लागू करने से जो असंगति उत्पन्न हुई है, वही आज ‘धर्मनिरपेक्षता बनाम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ की बहस का मूल कारण है।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पुनर्परिभाषा

योगी आदित्यनाथ का पूरा विमर्श भारतीयता की उस अवधारणा को पुष्ट करता है जिसमें व्यक्ति

की धार्मिक पहचान से पहले उसकी राष्ट्रीय पहचान को प्राथमिकता दी जाती है। यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के उस विचार से मेल खाता है जिसमें भारत की ‘सनातन संस्कृति’ को राष्ट्र के लोककल्याण का आधार माना गया है। उनके अनुसार, भारत की आदर्श स्थिति वह होगी जहाँ ‘धर्मनिरपेक्षता’ को केवल संवैधानिक शब्दावली तक सीमित न रखकर उसे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भों में देखा जाए। यह एक ऐसी जीवनशैली हो जो सहिष्णुता, विवेक और तार्किकता से युक्त हो, और सभी उपासना पद्धतियों को समान सम्मान देते हुए उन्हें भारतीयता की केंद्रीय धारा में समाहित करे। यह विचार उस ‘सामासिक संस्कृति’ को पुनः प्रतिष्ठित करता है जिसमें एक आम भारतीय अपनी धार्मिक प्रतिबद्धताओं के बावजूद दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता को पश्चिमी शब्दावली में नहीं, बल्कि भारतीय जीवन-मूल्यों में समझा जाना चाहिए इस परिप्रेक्ष्य में उनका वक्तव्य भारतीय संविधान और संस्कृति के बीच एक नए संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है — ऐसा संतुलन जिसमें संवैधानिक मूल्यों की रक्षा भी हो और सांस्कृतिक चेतना का सम्मान भी।

धर्मनिरपेक्षता का भारतीय पुनर्पाठ

यदि योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य को ‘धर्मनिरपेक्षता की भारतीय पुनर्व्याख्या’ के रूप में देखा जाए, तो इसके तीन आयाम सामने आते हैं —

1. दार्शनिक आयाम : भारतीय परंपरा में धर्म का अर्थ ‘सत्य-धारण’ और ‘कर्तव्य पालन’ है। इस अर्थ में राज्य का ‘धर्मनिरपेक्ष’ होना संभव नहीं, क्योंकि राज्य भी अपने कर्तव्य और न्याय के धर्म से बंधा है।
2. सांस्कृतिक आयाम : भारत की संस्कृति अनेक धर्मों, भाषाओं और आस्थाओं का संगम है। अतः धर्मनिरपेक्षता का भारतीय रूप ‘सह-अस्तित्व’ है, न कि ‘धर्म से दूरी’।

3. राजनीतिक आयाम :लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ केवल धार्मिक निष्पक्षता नहीं, बल्कि सबके प्रति समान व्यवहार है। यह तब तक संभव नहीं जब तक राजनीति धर्म का उपयोग पहचान और वोट के हथियार के रूप में करना बंद न करे।

इस दृष्टि से योगी आदित्यनाथ का तर्क केवल आलोचना नहीं, बल्कि आत्ममंथन का आमंत्रण है — कि क्या हमें धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी परिभाषा से आगे बढ़कर उसकी भारतीय आत्मा की खोज नहीं करनी चाहिए?

समाहार

योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य पर राजनीतिक और बौद्धिक जगत में तीखी प्रतिक्रियाएँ जारी हैं। समर्थकों के अनुसार, यह भारतीय संविधान के मूल भाव को भारतीय संस्कृति की दृष्टि से पुनर्परिभाषित करने का साहसिक प्रयास है। वे मानते हैं कि पश्चिमी राजनीतिक विचारों की अंधानुकरण से मुक्त होकर भारत को अपने अनुभवजन्य दर्शन पर आधारित राज्यर्शन विकसित करना चाहिए। विपक्षी दलों और उदारवादी बुद्धिजीवियों ने इसे संविधान की भावना

पर 'वैचारिक प्रहार' बताते हैं और आशंका जताते हैं कि भारतीयता की आड़ में हिंदुत्व की प्रस्थापना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। उनका कहना है कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय गणराज्य की आत्मा है — यदि इसे चुनौती दी गई तो भारतीय लोकतंत्र के बहुलतावादी स्वरूप पर संकट आएगा। परंतु एक तटस्थ विश्लेषक के रूप में यह कहा जा सकता है कि यह बहस न तो एकतरफा है और न ही समाप्त होने वाली। यह भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता का परिचायक है कि उसके मूल सिद्धांतों पर भी संवाद संभव है।

गाजीपुर से उठी यह वैचारिक लहर केवल उत्तर प्रदेश या बिहार तक सीमित नहीं रहेगी। यह उस राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनेगी जिसमें संविधान, संस्कृति और राजनीति के आपसी संबंधों पर नए प्रश्न उठेंगे। यदि इस विमर्श को रचनात्मक दिशा में ले जाया गया तो यह भारतीय राजनीति को विचारहीन नारों से ऊपर उठाकर वैचारिक आत्मविश्वास प्रदान कर सकता है। परंतु यदि यह केवल चुनावी ध्रुवीकरण का औजार बना, तो यह वही गलती दोहराएगा जिसे स्वयं योगी आदित्यनाथ 'धर्मनिरपेक्षता की विकृति' कहते हैं।

\*\*\*